ग्रीन रिवोल्ट
हरित-नीरा रहे वसुंधरा

पेजः 4
गिलोय : रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी

रविवारीय, 17 - 23 मई 2020 वर्ष- एक, अंक-41, रांची, कुल पृष्ठ 4 | हिन्दी साप्ताहिक | R.N.I. No. JHAHIN/2019/78094 | www.greenrevolt.news | मूल्यः 2 रूपये

ग्रीन रिवोल्ट के पाठकों से आग्रह है कि आप पर्यावरण, कृषि, जल संरक्षण, पशुपालन, बागवानी , पेट्स, वृक्षारोपण से संबंधित खबरें, समस्यायें, लेख, सुझाव, प्रतिक्रियायें या तस्वीरें हमें अवश्य भेजें। हमारा इमेल एवं ह्वाट्सएप नंबर है।
greenrevolt2019@gmail.com
9798166006

देश बनेगा आत्मनिर्भर और स्वदेशी ?

मनोज कुमार शर्मा

रांची : हाल ही में जब प्रधानमंत्री ने देश से स्वदेशी और आत्मनिर्भर होने का आह्वान किया तो एक नयी बहस छिड़ गयी । एक तबके का मानना है कि देश स्वदेशी नहीं और आत्मनिर्भर नहीं बन सकता और वो इस आह्वान और भारतीय क्षमताओं का उपहास भी उड़ा रहे हैं। वहीं एक बड़ी आबादी का ये मानना है कि कोरोना संकट ने हमें स्वदेशी आत्मनिर्भर बनने का मौका भी दिया है।

ये एक तथ्य है कि दो सौ साल पहले तक भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था में धाक था। यहां स्वदेशी उद्योगों से ही सभी आवश्यक चीजें बनायी जाती थीं और पूरा विश्व उसका उपभोक्ता था। तब इन उद्योगों के चलते ही देश में कोई बेरोजगार या वंचित नहीं था। गुलामी के समय अंग्रेजों ने हमारे इन सारे उद्योग धंधों को बर्बाद कर दिया। और ब्रिटेन की फैक्ट्रियों से बने आयातित उत्पादों पर हम निर्भर होते चले गये। हमारे मन में यह धारणा बनती चली गयी कि प्रत्येक विदेशी चीजें अच्छी होती हैं। हमने स्वनिर्माण को शिथिल कर दिया। इस सोंच का खामियाजा हम आज भी भुगत रहे हैं। पड़ोस में चीन ने निर्माण और स्वदेशी पर ध्यान केंद्रित किया और वह विश्व के बाजार में छाया हुआ है। मेड इन चाइना से पूरी दुनिया चकाचौंध है।

प्रधानमंत्री के इस आह्वान को हल्के में लेने के बजाय अगर हम स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को पूरा करने में लग जायें तो देश अपने स्वर्णिम काल को फिर से प्राप्त कर सकता है। आखिर प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण, सस्ते मजदूर, प्रचुर युवाशक्ति, तकनीकी दक्षता वाले भारत को अब तक किसने रोक रखा है स्वदेशी , आत्मनिर्भर होने से ?

पहले इन कमियों को दूर करना होगा

आत्मनिर्भर और स्वदेशी अपनाने का मतलब प्रत्येक चीज भारतीय हो ऐसा नहीं है। इसका एक ध्येय ये भी है कि विश्व की बड़ी कंपनियां भारत में अपना प्लांट लगायें, यहां के कच्चे माल का उपयोग करें और यहां के युवाओं को रोजगार मिले ।

प्रधानमंत्री ने कुछ साल पहले मेक इन इंडिया का नारा दिया था। और दुनिया की बड़ी कंपनियों को भारत में आकर निर्माण करने को कहा था। मेक इन इंडिया से अब तक हमें आशातीत रिजल्ट नहीं मिले हैं। दरअसल हमारी छवि विश्व में लालफिताशाही और कानूनी मकड़जाल में उलझाने वाली रही है। कल्पना किजिये कि अगर कोका कोला बनाने वाली अमेरिकी कंपनी के प्लांट को आंध्र पदेश में नक्सली विस्फोटक लगा कर उड़ा देते हैं तो इसका दूरगामी असर क्या होगा? विदेशी कंपनियां ऐसे में यहां क्यों आयेंगी? भारत में किसी प्लांट के लिये जमीन अधिग्रहण करना, उसके लिये लायसेंस लेना कानूनी मकड़जाल से पार पाकर उत्पादन शुरू करना अपने आप में दु:स्वप्न है। टाटा का बंगाल के सिंगुर में प्लांट लगाने का हश्र हम सभी देख चुके हैं।

झारखंड में कोरिया की एक कंपनी ने निवेश के अपने फैसले को एकाएक वापस ले लिया क्योंकि उसे समय पर जमीन उपलब्ध नहीं करायी गयी। झारखंड में भी मोमेंटम झारखंड का आयोजन हुआ था। ये शोध का विषय है कि सैकड़ो करोड़ खर्च करने के बाद भी राज्य में कितनी देशी विदेशी कंपनियों ने अपने प्लांट लगाये , कितनों को रोजगार मिला? जब तक देश में कानूनी मकड़जाल, ब्यूरोक्रेसी के फांस से लेकर प्रत्येक सुविधा को आसान और सहज नहीं किया जायेगा तब तक मेड इन इंडिया संभव नहीं। चीन जैसे देशों में यह समस्या नहीं रही इस लिये मेड इन चाइना आज सर्वत्र है। और हमने खादी बोर्ड के उत्पादों को भी सिर्फ एलिट क्लास का बना कर रख दिया।

खाद्यान्न में स्वदेशी ही बेहतर

देश का स्वास्थ्य बिगाड़ने में विदेशी खाद्य पदार्थो और विदेशी फूड प्रोसेसिंग प्लांट का भी बड़ा हाथ है जो खाद्य पदार्थों को देखने में आकर्षक बनाते हैं। पिज्जा बर्गर बनाने वाली एक विदेशी कंपनी ने हाइवे में अपने काउंटर खोले थे लेकिन उसकी बिक्री बहुत कम थी। उसने जब सर्वे करवाया तो उसे पता चला कि भारतीय हाइवे में ढाबों में खाना पसंद करते हैं न कि पिज्जा बर्गर। इसके बाद उसने ढाबों के खाने को खतरनाक बताना शुरू कर दिया था।

विदेशी पैकेटबंद भोजन और प्रोसेस्ड खाद्यान देश के स्वास्थ्य के लिये सही नहीं हैं। गांव में पारंपरिक तरीके से तैयार दलहन व अन्य अनाज ज्यादा शुद्ध और पौष्टिक होते हैं, उन्हें चमकाने के लिये किसी फूड प्रोसेसिंग प्लांट में हानिकारक तत्वों का उपयोग नहीं किया जाता।अब जहां तहां आटा चक्की घट रहे हैं और हम मिलावटी फाइबर रहित पैकेट बंद आटे का उपयोग कर रहे हैं।

सरकार का प्रयास हो तो दुनिया में छा सकता है मेड इन इंडिया

चीन के उत्पाद दुनिया भर में क्यों छाये हुये हैं और कोविड-19 से उत्पन्न संकटन ने हमें कैसे एक अवसर भी उपलब्ध कराया है ये । इस अवसर को भुनान से पहले विश्व की बड़ी कंपनियों, उनके उत्पाद और चीन जैसे देशों में उनके निर्माण को समझना होगा।

सैमसंग , एप्पल कोरिया और अमेरिका की कंपनियां हैं। इन्होंने सस्ते श्रम और कम लागत के लिये चीन में अपने मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट लगा रखे हैं। चीन में बनाना या असेंबल करना इन्हें सस्ता पड़ता है और चीन की सरकारों ने भारत की तरह इन विदेशी कंपनियों को लालफिताशाही और कानूनों के मकड़जाल में उलझाने के बजाये सारी सुविधायें सहजता से उपलब्ध करायी हैं। इसी कारण से हजारो ऐसी कंपनियां जो अमेरिका, जापान, कोरिया, ब्रिटेन की हैं उन सबों ने चीन में उत्पादन शुरू कर दिये। यहां से ये उत्पाद भारत समेत दुनिया भर में सप्लाई हो रहे हैं। कंपनी भले अमेरिका की है, पर चीन में बनने के कारण इनपर मेड इन चाइना लिखा जाता है। सस्ते श्रम और भारत जैसे बड़े बाजार के कारण चीन दुनिया भर के बड़ी कंपनियों का मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है और दुनिया मेड इन चाइना उत्पादों से अटी पड़ी है। मामूली खिलौने से लेकर एप्पल के आइफोन तक सभी मेड इन चाइना हैं।

चीन ने अपने प्रमुख शहरों से रेल लाइन का सुदूर यूरोप के शहरों तक नेटवर्क बिछा रखा है

यहां एक पेंच और है कि अमेरिकन कंपनी के उत्पाद ही जब चीन में बनते हैं तो उपभोक्ता के अनुसार उसकी क्वालिटी मे अंतर भी रहता है। चीन निर्मित उत्पाद यूरोप और अमेरिका के लिये अलग गुणवत्ता के और भारत जैसे देशों के लिये घटिया गुणवत्ता के होते हैं। और कुछ यूरोपीय और अमेरिकी कंपनियां चीन में बने अपने ही उत्पादों को खुद अपने देश में उपयोग नहीं करतीं ये अपने उपयोग के लिये खुद के देश में ही बने अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद को उपयोग करती हैं।

लॉकडाउन के कारण और चीन की हालिया करतूतों से दुनिया भर के सारे देश नाराज और खिन्न हैं उनका चीन से अपने मैन्युफैक्चरिंग के काम को समेटने का प्लान है और वो भारत का रूख करना चाह रही हैं। 300 कंपनियों ने चीन से सब कुछ समेट कर भारत में मेक इन इंडिया की इच्छा जतायी है और सरकार से सुविधायें देने की मांग भी की है। अगर ऐसा हुआ तो जानकारों का कहना है कि भारत में भी सस्ते श्रम के कारण चार हजार कंपनियां चीन को छोड़ कर आ सकती हैं। इससे यहां रोजगार की बाढ आ जायेगी और मेड इन इंडिया का जलवा दुनिया को देखने को मिलेगा। लेकिन इससे पहले भारत को इन विदेशी कंपनियों के लिये सब कुछ सहज करना पड़ेगा और कानूनी मकड़जाल से लेकर लालफिताशाही को खत्म करना होगा, देश में निर्माण के लायक माहौल तैयार करना होगा, ट्रांसपोर्ट से लेकर, बिजली, कानून व्यवस्था सब कुछ ठिक करना होगा।

जानवरों को छोड़ने की घटनायें बढीं

जानवरों के लिए काम करने वाले एनजीओ और कार्यकर्ताओं का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान जानवरों को छोड़ देने की घटनाएं बढ़ी हैं। उनके मुताबिक ऐसा इसलिए क्योंकि कुत्तों और बिल्लियों के लिए शेल्टर होम लॉकडाउन की वजह से बंद हो गए हैं। यही नहीं आवारा जानवरों के साथ इस दौरान क्रूरता के मामले भी बढ़े हैं। कई बार तेज रफ्तार गाड़ियां भी उन्हें टक्कर मार दे रही है।

पीपल फॉर एनिमल ट्रस्ट जो भारत का सबसे बड़ा पशु कल्याण संगठन है, वह रोज जख्मी और मेडिकल मदद की जरूरत वाले आवारा जानवरों के लिए कैंप लगाता है । इस संगठन के 36 अस्पताल हैं और ढाई लाख के करीब सदस्य हैं। संगठन के सदस्य कोविड-19 के खतरे के बावजूद बाहर निकल आवारा कुत्तों को भोजन दे रहे हैं।

भूंगरू जल संचयन विधि को स्टार्टअप सम्मान

जेएससीए स्टेडियम में भी रथिन भद्रा और राजा बागची ने खास तकनीक से जल संकट दूर किया

भूंगरू वह नायाब तकनीक जो जलसंकट को कर सकता है समाप्त

भूंगरू जल संचयन की स्वदेशी तकनीक है। जिसे झारखंड के दो युवाओं रथिन भद्रा और राजा बागची ने विकसित किया है इस पर ग्रीन रिवोल्ट ने एक विस्तृत रिपोर्ट एवं साक्षात्कार 15 सितंबर 2019 अंक में प्रकाशित भी किया था। भूंगरू अपनी खास विधि से जल रहित सूखे क्षेत्रों में भी भू जलस्तर को बढ़ा कर वहां जलसंकट को दूर कर देता है इससे सूखाग्रस्त गांवों और जलसंकट से जूझ रहे जगहों को जल के रूप में प्राणवायु मिला है।

संवाददाता

रांची : झारखंड के लिये यह बहुत ही गर्व का विषय है कि राज्म में जल संचय की अनूठी और बेहद सफल तकनीक *भूंगरू* के आविष्कारक रथिन भद्रा एवं राजा बागची को सम्मानित किया गया है। इन्हें इन्नोवेटिव आईडिया के साथ झारखंड के एक उभरते हुये स्टार्टअप का सम्मान मिला है।

अटल बिहारी वाजपेयी इनोवेशन लैब जिसे की झारखंड इनोवेशन लैब नाम से भी जाना जाता है जो डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी & e-गवर्नेंस झारखंड सरकार के अंदर आता है , उन्होंने कई चरणों के साक्षात्कार और प्रस्तुतिकरण तथा मूल्यांकन के बाद कई वैज्ञानिकों , प्रॉफेसनल्स , आइआइएम अहमदाबाद की टीम तथा आईएएस की टीम की पूरी जांच पड़ताल के बाद *भूंगरू* जल संचयन तकनीक को इन्नोवेटिव आईडिया के साथ झारखंड के एक उभरता हुआ स्टार्टअप पाया और टीम भूंगरु को ऑफिसियली स्टार्टअप झारखंड का प्रमाणपत्र भी दिया इन्हें झारखंड सरकार अटल बिहारी वाजपेयी इनोवेशन लैब के ऑफिसियल वेबसाइट पर जगह भी दी गई।

गांव वालों का आशिर्वाद ही हम दोनो की असली कमाई है:रथिन भद्रा,राजा बागची

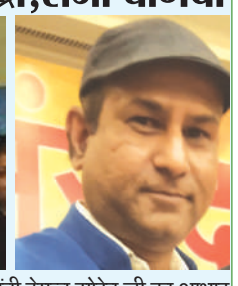

आज हम दोनों पलामू के लाल राजा बागची और रथिन भद्रा के लिए गर्व का दिन है की हमको हमारी अपनी जन्मभूमि, झारखंड में सम्मानित किया गया है। और हमें भी यह संतोष है कि हमने अपने जन्मभूमि के लिये कुछ किया। मैं अपने मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन जी का आभार व्यक्त करता हु की वे झारखंडियों को आगे बढ़ने के लिए हर सम्भव कोशिश कर रहे है और प्लेटफार्म भी दे रहे है । मैं आईएएस मनोज कुमार जी जो कि उस समय के रांची डीसी थे उनका दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हु जिहोने इस प्रोजेक्ट को समझने के साथ ही संकल्प लेकर भूंगरु प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। इन्ही का प्रयास था कि स्टेट प्लानिंग तथा योजना सह वित्त विभाग में ये प्रोजेक्ट गया। मैं हमारे मुख्य सचिव सुखदेव सिंह जी का भी हृदय से धन्यवाद करना चाहता हु क्योंकि वे ही एक व्यक्ति थे जिहोने हम लोगो का पहला प्रोजेक्ट को पास किया था और कहा था कि सरकार अरबो रुपये अलग-अलग चीजो में खर्च करती है एक अगर साइंटिफिक प्रोजेक्ट आया है जल संचयन का तो एक बार मौका दे के तो देखे , ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि सफलता हाथ नहीं लगेगी? यही तो इन्नोवेशन है हम मौका देकर प्रयास तो कर ही सकते हैं। एक वो दिन था और एक आज का दिन है कि टीम भूंगरु ने जहां-जहां भी जल संचयन "पानी की खेती" का काम किया वो न सिर्फ सफल हुआ बल्कि उसका उपयोग करने वाले लोगों ने, बच्चों ने हृदय से हमे आशिर्वाद दिया। लोगो का यही आशीर्वाद हमारी कमाई है ।

कोल इंडिया का निजीकरण नहीं: प्रल्हाद जोशी

संवाददाता :केन्द्रीय कोयला एवं खान मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किए गए एलान से कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) में बुनियादी - विकास के लिए 50 हजार करोड़ रूपये के निवेश का फैसला लिया गया है। इस फैसले से कोल इंडिया को वित्त वर्ष 23-24 तक अपने 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने की राह आसान होगी। कोल इंडिया के लिए यह एक बड़ा अवसर है जब कंपनी नई खदानें खोलते हुए अधिक से अधिक कोयला उत्पादन कर देश में हो रहे कोयले के आयात की भरपाई कर सकती है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में कोल इंडिया अपने उत्पादन से सालाना 100 मिलियन टन कोयले के आयात की भरपाई करेगी। उन्होंने एक बार फिर जोर देकर कहा कि सरकार का कोल इंडिया के निजीकरण का कोई इरादा नहीं है, बल्कि सरकार कोल इंडिया को मजबूत कर रही है और इसे आगे भी और मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि कंपनी के पास पर्याप्त कोयला भंडार है, जो देश में 100 वर्षों से अधिक तक बिजली बनाने के लिए पर्याप्त है। हाल ही में सरकार ने कोल इंडिया को 16 नए कोयला ब्लॉक भी दिए हैं।

कोल इंडिया परिवार को आश्वस्त करते हुए प्रल्हाद जोशी ने कहा कि सरकार को कोल इंडिया पर गर्व है और आने वाले समय में इसे और मजबूत किया जाएगा।

कोरोना से जंग में रोल मॉडल बन कर उभरा है रांची: हेमन्त सोरेन

संवाददाता

रांची : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि आज राँची देश के समक्ष कोरोना से इस जंग में एक रोल मॉडल बन कर उभरा है। इसका पूरा श्रेय रांची जिला प्रशासन, डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिसकर्मियों, सफाई कर्मियों एवं बिना स्वार्थ भाव से जनता की सेवा कर रही समाजसेवी संस्थाओं को जाता है। ना सिर्फ रांची ने कोरोना से जंग जीती है, बल्कि सामाजिक सौहार्द की भी अनूठी मिसाल कायम की है। स्मरण रहे, हम साथ मिलकर ही इस महामारी को हरा सकते हैं। इसलिए पुनः आग्रह आपस में दूरी बनाएं पर दिलों को जरूर जोड़े रखें।

रांची में कोरोना ज्यादतर कोरोना पोजीटीव मरीज ठीक हो चुके हैं और जिले में मरीजों की संख्या बहुत कम रह गयी है

इसलिए कहा रांची ने मिशाल कायम की...

मुख्यमंत्री को जानकारी मिली कि देश के विभिन्न शहरों की तुलना में रांची का रिकवरी रेट (कोरोना संक्रमण के मामले में) सबसे अधिक है। रांची में कोरोना संक्रमण के 104 मामले मिले, जिसमें 83 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। अब कोरोना संक्रमण के 21 सक्रिय मामले ही शेष हैं। यही गति रही तो रांची आनेवाले कुछ दिनों में रेड जोन से बाहर हो जाएगा।

मौसम में बदलाव, झारखण्ड में मौसमी पहचान की वापसी के संकेत

डॉ अब्दुल वदूद

रांची दशकों पहले झारखण्ड की गर्मी अप्रैल से मई माह में बहुत ही सुखद हुआ करता था। मार्च से मई के तीन महीनों में सामान्यतः करीब 150 - 160 मिली मीटर बारिश हो जाया करती थी। अक्सर प्रथम बेला में थोड़ी गर्मी होने के बाद दुसरे बेला में बारिश होती थी। एक दो दिनों के अंतराल पर बारिश होने से घटते तापमान से लोगों को गर्मी की मार से राहत मिलती थी। इस बारिश से खेतों में भी अच्छी खासी नमी मौजूद होती थी। खेतों में मौजूद इस नमी का फायदा किसानों को मिलता था। किसानों को बड़ी आसानी से खेतों को जुताई करने में मदद मिलती थी। जुन माह के प्रथम सप्ताह में मानसून के आगमन के साथ ही किसान बिना समय गंवाए ससमय खरीफ फसलों की बुवाई करते थे। इसी समय रोपा धान के लिए जरूरी बिचड़ों के लिए नर्सरी की भी तैयारी शुरू हो जाती थी।

पिछले 12-15 वर्षो (2005-06) के बाद से ही प्रदेश के मौसम की यह विशेष पहचान लगभग विलुप्त सी हो गयी थी। शायद वैश्विक एवं स्थानीय मौसम परिवर्तन इसकी वजह हो। इन 12-15 वर्षो के तीन महीनों में 50 - 60 मिली मीटर मात्र बारिश होती रही है। इसकी वजह से किसान अपने खेतों की तैयारी समय पर बिलकुल नहीं कर पाते थे।ऐसी स्थिति में मानसून के सही समय पर आने के बावजूद खरीफ फसलों की बुवाई में देरी हो जाती थी। इसके आलावा दिन का अधिकतम तापमान 42-48 डिग्री सेल्सियस हप्तो तक बना रहता।इससे प्रदेश की बहुतायत एकफसली कृषि व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। जल संकट की विकट स्थिति से किसानों के साथ आम लोगों की भी परेशानी बढ़ी। किसानों को जीवन यापन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस वर्ष मौसम की परिस्थितियाँ बिलकुल बदली बदली सी है। झारखण्ड की मौसमी पहचान लौटते हुए प्रतीत हो रहा है। अब तक लोगों को गर्मी से निजात मिल रहा है। बीएयू के मौसम विभाग के कांके के आँकड़ों के मुताबिक इस वर्ष पहली अप्रैल से 10 मई तक 91 मिली मीटर बारिश हो चुकी है। इस वर्ष 1 मार्च से 10 मई तक काफी अच्छी होने से किसानों को खेतों में काफी राहत मिली है। किसान खेतों की बड़ी आसानी से तैयारी कर पा रहे है। जबकि गत 2017-19 के वर्षो में पहली अप्रैल से 30 मई तक औसत वर्षा 61 मिली मीटर मात्र ही दर्ज की गई। इस वर्ष दिन का तापमान भी 33 - 35 डिग्री सेल्सियस के आस-पास बना हुआ है। जो विशेषकर 19 अप्रैल से 10 मई तक देखी गई है।

गत तीन वर्षो के औसत अधिकतम तापमान की तुलना में वर्तमान के अधिकतम तापमान में निरंतर 3-7 डिग्री सेल्सियस कमी देखी गई है। मानव शरीर के लिए सहज तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक है और इससे अधिक तापमान होने पर बेचनी महशुश होने लगती है। वर्तमान में लोग गर्मी से राहत महसूस कर रहे है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पुर्वानुमान के मद्देनजर पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मानसून के आगमन तक मौसम की यह स्थिति बनी रहेगी। इस वर्ष मानसून में अच्छी वर्षा होने के संकेत मिल रहे है।

मौसम में वांछित बदलाव से झारखण्ड के लोग, किसान, कृषि विभाग और मौसम वैज्ञानिक आगामी खरीफ की अच्छी खेती के प्रति काफी आशावान है। इस बदलाव को झारखण्ड के कृषि परिदृश्य के लिए एक शुभ संकेत माना जा सकता है। हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, पर झारखण्ड की मौसमी पहचान लौटती हुई जरूर प्रतीत हो रही है। आने वाले वर्षो में मौसम की ऐसी पुनरावृति होता रहे, तो यह प्रदेश में कृषि क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी बात होगी। इस वर्ष मौसम में इन वांछित बदलाव के कारणों का वैज्ञानिक आकलन किया जाना बाकी है। कोविड - 19 के चलते 25 मार्च से चल रहे लॉकडाउन का भी इसमें बड़ा योगदान माना जा सकता है। क्योंकि इस अवधि में पर्यावरण से छेड़ - छाड़ निम्न स्तर पर है। साथ ही हवाई, रेल, सड़क और समुद्री यातायात बंद होने से प्रदूषण में भारी कमी से बेहतर पर्यावरण का सुख मिल रहा है।

स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में भी यदि हम पर्यावरण को कम से कम छेड़ते हुए प्रदूषण को निम्न स्तर पर बनाये रखने में सक्षम हो पाए, तो फिर वह दिन दूर नहीं जब हम पर्यावरणीय एवं मौसमी परेशानी से निजात पाने में सफल होंगे।

लेखक कृषि मौसम एवं पर्यावरण विभाग बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, रांची में अध्यक्ष हैं

मत्स्य किसान प्रशिक्षण केंद्र का किया अवलोकन

रांची : पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखंड सरकार अबूबकर सिद्दिकी ने मत्स्य अनुसंधान केन्द्र सह मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र शालीमार , धुर्वा , रांची का अवलोकन किया। निदेशक मत्स्य झारखंड रांची डॉ. एच.एन. द्वीवेदी ने विभाग के क्रिया कलापों की जानकारी दी और विभाग के पिछले वर्ष की उपलब्धियों तथा नये वर्ष के कार्य परियोजनाओं कर विस्तृत जानकारी दी। डॉ. एचएन द्वीवेदी ने बताया कि झारखंड में मत्स्य उत्पादन का कार्य बहुत ही अच्छी तरह से हो रहा है और केन्द्र सरकार द्वारा घाषित सहायता प्राप्त होने पर झारखंड में मत्स्य पालन को और गति मिलेगी।

पैकेज पर जनता का कितना भरोसा?

प्रधानमंत्री ने बीस लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा कर दी। सत्ता पक्ष इसे लेकर खुद अपनी पीठ थपथपा रहा है उसका कहना है कि कोरोना महामारी से देश में आये संकट से निबटने के लिये सरकार कुल जीडीपी का दस प्रतिशज पैकेज के रूप में दे रही है। विपक्ष हमेंशा की तरह सही सवाल पूछने के बजाय विरोध कर अनाप शनाप राय दे रहा है। कोई कह रहा है कि पैकेज के बजाय प्रत्येक परिवार को साढे सात हजार रूपये कैश दे दिये जायें। इन सब के बीच जनता है के मन में ये सवाल उठ रहा है कि ये बीस लाख करोड़ क्या सचमुच खर्च होंगे? और अगर होंगे तो उससे हमें किस तरह लाभ मिलेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि हर बार की तरह ये राशि बीच में हीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ जायेगी और जमीन पर कुछ खर्च नहीं होगा? देश में इन मामलों में सरकार और जनता के बीच संवाद और समझ में इतने अवरोध हैं कि जनता कुछ समझ नहीं पाती और अंततः ये मान लेती है कि ये सब झूठ है या लूट की भेंट ही चढ़ जायेगा।

जनकारों का कहना है कि चार दिन तक सिलसिलवेार वित्तमंत्री निर्मला सीतारामण और अनुराग ठाकुर ने टीवी में आकर अंग्रेजी हिन्दी में पैकेज के बारे में हिसाब बताये उनमें से बहुत सारी योजना राशि पहले से ही बजट में शामिल है। और इनमें कुछ बातें अच्छी भी हैं जैसे अब दूसरे राज्यों में जाकर भी किसान अपनी उपज को बेच सकेंगे, स्टॉक करने की सीमा भी अब निर्धारित नहीं है। पर बार बार सवाल घूम फिर कर वहीं आ जाता है कि ये पैकेज जमीन पर कितना उतरेगा? किन माध्यमों से उतरेगा और वो माध्यम पाक साफ हैं?

अब ये सरकार की जिम्मेवारी है कि इस पैकेज को जमीन पर उतारे वर्ना लोग हमेंशा की तरह इसे मजाक ही समझते रहेंगे।

जनता सरकार के अरबो खरबों के पैकेज को एक मजाक मान कर चलती है। जब पीड़ित और लाचार आबादी वित्तमंत्री के अंग्रेजी भाषण उसके बाद अनुराग ठाकुर के हिंदी अनुवाद को चार किश्तों में सुन चुकी है तो उसके मन में पहला सवाल यही उठता है कि इन्होंने आखिर क्या कहा? क्या अरबो खरबो रूपये सचमुच अलग-अलग सेक्टरों में ठोस रूप में खर्च होंगे? और जनता खुद उसका जवाब भी देती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला।

खरबों रूपये गरीबी हटाने के नाम पर बजट में सुन सुन कर लोग इतने पक चुके हैं कि उन्हें सरकारी मंशा सही भी हो तब भी भरोसा नहीं होता। इस बीच खबर है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का सरकार पर 16000 करोड़ बकाया है।

पृथ्वी के मौसम पर चंद्रमा का क्या असर होता है?

सौरमंडल में बृहस्पति के पास सबसे ज्यादा 79 चांद हैं। इसके बाद 62 चंद्रमा वाले शनि की बारी आती है। वहीं बुध और शुक्र के पास कोई चंद्रमा नहीं है। और धरती का केवल एक चांद है जिसका हमारे ग्रह के मौसम से गहरा संबंध है। यूरोप में कुछ लोग जंगलों में जा कर मशरूम जमा करने का शौक रखते हैं। ये लोग बताते हैं कि पूर्णिमा की रात के बाद अगले दिन उन्हें बढ़िया क्वॉलिटी के मशरूम मिलते हैं। इन मशरूमों में कीड़े लगभग नहीं के बराबर होते हैं। मशरूम जमा करने वालों के मुताबिक पूर्णिमा की रात अन्य रातों के मुकाबले ठंडी होती है। और यह बात सही है। लेकिन रात चंद्रमा की वजह से ठंडी नहीं रहती। इसकी वजह है बादलों का ना होना। बादल छाए होने की वजह से दिन में पड़ने वाली गर्मी पृथ्वी पर ही रह जाती है। जब आसमान साफ होता है, तो गर्मी आसानी से अंतरिक्ष में चली जाती है और धरती ठंडी हो जाती है। लेकिन चंद्रमा मौसम को प्रभावित करता है? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से ही समुद्र में ज्वार उठता है। ज्वार भाटे से पानी में बड़ी हचलच होती है जिससे हीट बफर बनता है और मौसम प्रभावित होता है। माना जाता है कि अगर ज्वार ना उठें तो पृथ्वी तीन गुना तेजी से घूमेगी। इसके गंभीर परिणाम होंगे। मसलन वातावरण में टरब्यूलेंस बढ़ेगा। इससे तूफान बढ़ेंगे जिनकी रफ्तार 500 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है जिससे भारी तबाही होगी। गर्मियों में तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। वहीं सर्दियों में पारा मायनस 50 डिग्री तक गिर सकता है।

चंद्रमा सिर्फ पृथ्वी के घूमने के क्रम को ही नहीं तोड़ता, बल्कि यह उसकी कक्षा में अक्षों को भी स्थिरता देता है। साथ ही चंद्रमा हमारे नीले गृह पर मौसम को स्थिर भी बनाता है। इसीलिए भूमध्यरेखा वाले इलाकों में पूरे साल एक जैसा मौसम रहता है। खूब सूरज चमकता है। पूरे साल यहां गर्मी रहती है और रोज बारिश होती है। बहुत से जीवों के लिए यह इलाका जन्नत जैसा है। वहीं पृथ्वी के ध्रुवों पर सर्दियों के महीनों में रातें घुप अंधेरी होती हैं और तापमान इतना कम कि इंसानों के लिए रहना मुश्किल हो जाए। चंद्रमा के बिना पृथ्वी लड़खड़ाने लगती। इससे ना सिर्फ दुनिया के मौसम पर, बल्कि जलवायु पर भी दीर्घ कालीन प्रभाव पड़ते। इससे ना सिर्फ पेड़ पौधे, बल्कि इंसानों की जिंदगियों को भी खतरा होता। इसलिए शुक्र मनाइए कि हमारी पृथ्वी के पास चंद्रमा है।

जानवरों में भी नरों से ज्यादा जीती हैं मादायें

अगर ठीक से रहने दिया जाए तो महिलाएं पुरुषों से औसतन छह से आठ साल ज्यादा जीती हैं। अब पता चला है कि यह बात कई जंगली जानवरों के लिए भी सही है। यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ के जीवविज्ञानियों समेत अंतरराष्ट्रीय रिसर्चरों की एक टीम ने जानवरों की 101 किस्मों के जीवनकाल पर शोध कर इसका पता लगाया है। यह स्टडी 'प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस' में प्रकाशित हैरान करने वाले नतीजों पर नजर डालिए। जानवरों की दुनिया में नर और मादा के लाइफ स्पैन में अंतर इंसानों से काफी बड़ा है। स्टडी में शामिल किस्मों में से करीब 60 फीसदी में मादाओं की उम्र नरों से औसतन 18 प्रतिशत लंबी रही। इंसानों में महिला और पुरुषों में यह अंतर करीब 8 फीसदी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, इसकी वजह यह है कि सेहत के मामले में महिलाएं जैविक रूप से पुरुषों से बेहतर होती हैं और वे औसतन लंबा जीवन जीती हैं।

घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों का क्या होगा?

मुरली कृष्णन

लॉकडाउन के दौरान लाखों प्रवासी मजदूरों की वापसी पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच रार मची हुई है, जबकि मजदूर अभी भी पैदल और चोरी-छिपे घर आने को मजबूर हैं। एक बड़ा सवाल यह भी है कि इन मजदूरों का आगे का जीवन कैसे चलेगा?

लॉकडाउन की वजह से अलग-अलग राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए राज्य सरकारों ने अपनी ओर से पहल की है तो तमाम हील-हवाले और राज्यों के अनुरोध पर रेल मंत्रालय ने भी इन मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। एक ओर ट्रेन के किराये पर जमकर विवाद हो रहा है तो इन श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से आने वाले ज्यादातर मजदूरों की शिकायत है कि उनसे न सिर्फ किराया वसूला गया बल्कि कई घंटों की यात्रा के दौरान वो भूखे-प्यासे रहे। वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में मजदूरों के लौटने से पंजाब, हरियाणा और कर्नाटक जैसे कई राज्यों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं।

पंजाब और हरियाणा सरकार ने तो मजदूरों से वहीं रुकने और अपने घरों को न जाने का अनुरोध किया और किसी तरह की दिक्कत न होने का भरोसा दिया जबकि कर्नाटक सरकार इससे दो कदम आगे निकल गई और मजदूरों को भेजने के फैसले को ही पलट दिया। लेकिन चहुंओर इस फैसले पर उठते सवालों के बाद राज्य सरकार ने अपना फैसला फिर बदल दिया और ट्रेनों को जाने की अनुमति दे दी। विभिन्न राज्यों से यूपी और बिहार में लौटने वाले वे मजदूर हैं जो उन राज्यों में चौदह दिन की क्वारंटीन अवधि पूरी कर चुके हैं। हालांकि इन्हें अपने गृह जनपदों में घरों तक जाने के पहले टेस्टिंग से गुजरना होगा और ये घरों तक कब पहुंच पाएंगे, तय नहीं है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ी समस्या यह है कि अपनी नौकरी और छोटे-मोटे रोजगार छोड़कर आए ये मजदूर अब अपने घरों पर क्या करेंगे और जीवन निर्वाह कैसे करेंगे?

उत्तर प्रदेश की सरकार ने बाहर से आने वाले श्रमिकों को राज्य के भीतर ही काम देने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को रोजगार की व्यापक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार प्रदेश के सभी 7 लाख प्रवासी मजदूरों को वापस लाना चाहती है। आने वाले प्रत्येक श्रमिक और कामगार का सरकार स्किल डाटा तैयार करा रही है और होम क्वारंटीन पूरा होते ही यूपी के अंदर ही उन्हें रोजगार दिलाने की तैयारी की जा रही है। एक जिला एक उत्पाद यानी ओडीओपी योजना के जरिये हस्तकला में प्रशिक्षित प्रवासी मजदूरों को गांवों में ही काम मिल जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे कितने मजदूर हैं जो ओडीओपी जैसी योजना में योगदान देने के लिए प्रशिक्षित हैं। ज्यादातर मजदूर अन्य राज्यों में या तो औद्योगिक प्रतिष्ठानों में काम कर रहे थे, घरेलू कार्यों में लगे थे या फिर प्राइवेट कंपनियों में नौकरी कर रहे थे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों भी श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक समिति गठित करने के निर्देश दिए थे। यह समिति बैंकों के जरिये ऋण मेले और रोजगार मेले भी आयोजित कराएगी ताकि लोगों को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर मुहैया कराए जा सकें। समिति एमएसएमई के तहत विभिन्न उद्योगों में रोजगार के अवसर सृजित करने की संभावनाएं भी तलाशेगी। राज्य सरकार ने बाहर से लौटे मजदूरों को मनरेगा के तहत काम देने के लिए जरूरी जॉब कार्ड भी तुरंत बनवाए जाने के निर्देश दिए हैं ताकि गांवों में जल्द ही मनरेगा के तहत काम शुरू कर दिया जाए।

कैसे मिलेगा लोगों को काम?

यह कितना संभव हो पाएगा, इसे लेकर जानकारों को संशय है। पहली बात तो यह कि सरकार ने उन सात लाख प्रवासी श्रमिकों के हिसाब से कार्ययोजना तैयार करने को कहा है, जो उसकी नजर में अन्य राज्यों में काम छिन जाने के बाद आए हैं। जबकि श्रमिकों की यह संख्या इससे कहीं ज्यादा है। दस लाख से ज्यादा श्रमिक तो सिर्फ मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों से आए हैं। दरअसल, सरकार के पास सिर्फ वो आंकड़े हैं जो उसके साधनों से आए, जबकि अपने आप आने वालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है। वरिष्ठ पत्रकार अरविन्द कुमार सिंह कहते हैं कि इसके लिए पंचायतों को और अधिक मजबूत, सशक्त और आत्म निर्भर बनाना पड़ेगा। वे कहते हैं, "सरकार को यह डाटा बेस तैयार करना होगा कि किन क्षेत्रों में कौन से लोग खासतौर पर प्रशिक्षित हैं।" बताया जा रहा है कि सरकार की ओर से गठित समिति इस बात की भी संभावनाएं तलाशेगी जिससे कुछ छोटे उद्योगों को ग्रामीण स्तर पर भी स्थापित किया जा सके और श्रमिकों को आस-पास ही काम मिल सके।

श्रमिक नेता राम अधार पांडेय बताते हैं, "उत्तर प्रदेश में पहले बड़ी संख्या में छोटी-बड़ी फैक्ट्रियां थीं और निजी स्तर पर भी तमाम कारखाने थे। धीरे-धीरे ये सब बंद होते गए और लोगों को रोजी-रोटी के लिए महानगरों का रुख करना पड़ा। यदि लोगों को आजीविका के लिए अपने क्षेत्र में ही काम मिलने लगे तो भला घर-परिवार को छोड़कर बाहर कौन जाना चाहेगा।'' ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव अमरजीत कौर कहती हैं, "लॉकडाउन की स्थिति में सबसे जरूरी तो यह है कि मजदूरों को वित्तीय सहायता दी जाए ताकि वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। नेशनल रजिस्टर बने ताकि प्रवासी श्रमिकों का ब्यौरा दर्ज हो और उनका डाटा शेयर किया जाए और उनके हितों की रक्षा हो सके। होटल, सिनेमा, ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे मजदूरों के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाएं ताकि इन क्षेत्रों में लगे श्रमिकों का इस्तेमाल भी हो सके और वो आर्थिक रूप से पंगु भी न होने पाएं।''

मजदूरों को वायदों पर भरोसा नहीं

राज्य सरकार ने लॉकडाउन के तीसरे चरण के साथ ही एक्सप्रेस वे और कुछ दूसरे निर्माण कार्यों को खोलकर श्रमिकों को समायोजित करने की कोशिश की है लेकिन इनमें उन्हीं श्रमिकों को काम मिला है जो पहले से यहीं काम कर रहे थे। राज्य सरकार अभी योजना बना रही है, उसके बाद उसे क्रियान्वित करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़े विश्वास के साथ कहा है कि वो दूसरे राज्यों से आए श्रमिकों को अपने ही राज्य में काम देंगे, लेकिन बाहर से आए श्रमिक अभी इस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा 'मोना' राज्य सरकार की इन कोशिशों में गंभीरता नहीं देखती हैं। उनका कहना है कि लॉकडाउन लागू हुए डेढ़ महीने से ज्यादा बीत चुके हैं और सरकार अभी मजदूरों की समुचित वापसी का भी प्रबंध नहीं कर सकी है। मजदूर अभी भी अपने घर पहुंचने के लिए इधर-उधर भटक रहे हैं। ऐसे में सरकार उनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था करेगी, इसमें संदेह है। यूपी में लाखों की संख्या में बेरोजगार लोग पहले ही घूम रहे हैं, करीब 16 लाख श्रमिकों की वापसी के बाद उन्हें सरकार काम दे देगी, इस पर विश्वास करना मुश्किल है।

पंजाब से बरेली आए श्रमिकों का कहना था कि अभी तो उन्हें 14 दिन क्वारंटीन में रहना है, उसके बाद काम की सोचेंगे। वहीं दिल्ली की एक ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करने वाले प्रतापगढ़ के निवासी रघुवीर दयाल बेहद गुस्से में कहते हैं, "काम मिले न मिले, बाहर मजदूरों की जो दुर्दशा हुई और जैसा अपमान हुआ, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया, उसे देखते हुए लगता नहीं कि ये लोग लौटकर फिर कहीं काम के लिए जाएंगे। मैं तो अब जीवन में कभी दिल्ली नहीं जाऊंगा। हम अपने गांव में रहकर खेती करके जिंदगी चला लेंगे लेकिन बाहर नहीं जाएंगे। ●

कितना सही है कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा?

एजेंसियां : दुनिया भर में 30 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और दो लाख से भी ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। लेकिन मौतों का यह आंकड़ा कितना सही है? हर दिन दुनिया भर में कोरोना के कारण मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। रोज हजारों लोग इसका शिकार हो रहे हैं। लेकिन आंकड़ों को दर्ज करने के लिए हर देश कुछ अलग तरीका अपना रहा है। ऐसा नहीं है कि इलाज और सावधानी बरतने के डब्ल्यूएचओ के प्रमाणित तरीकों की तरह आंकड़े जमा करने का भी कोई एक तरीका है। ऐसे में इन आंकड़ों की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लगा हुआ है।जर्मनी, स्पेन, दक्षिण कोरिया और लक्जमबर्ग में हर उस व्यक्ति को कोविड-19 के कारण मरने वालों की सूची में डाला जाता है जिसका कोरोना टेस्ट का नतीजा पॉजिटिव रहा हो। फिर चाहे उस व्यक्ति की मौत अस्पताल में हो या फिर घर में। वहीं बेल्जियम में आधी से ज्यादा मौतें नर्सिंग होम में हुई। यहां उन लोगों को भी सूची में रखा गया जिन पर कोरोना होने का शक था लेकिन उनके टेस्ट नहीं हुए थे। फ्रांस में भी एक तिहाई मौतें नर्सिंग होम में ही हुई।चीन और ईरान में केवल उन लोगों को सूची में रखा गया जिनकी मौत अस्पताल में हुई। घर में मरने वालों का आंकड़ा इसमें शामिल नहीं किया गया। कुछ ऐसा ही हाल ब्रिटेन का भी है। वहां ऑफिस फॉर नेशनल

स्टैटिस्टिक्स हर हफ्ते आंकड़े प्रकाशित कर रहा है लेकिन दस दिन पुराने। साथ ही इनमें स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के मामलों का कोई जिक्र नहीं है।यूरोप में सबसे ज्यादा मौतें इटली में हुई। लेकिन आधिकारिक रिकॉर्ड दिखाते हैं कि सिर्फ बड़े वृद्धाश्रमों को ही सूची में जोड़ा गया था। वहीं अमेरिका में, जहां दुनिया की सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, हर राज्य का तरीका दूसरे राज्य से अलग है। मिसाल के तौर पर न्यूयॉर्क नर्सिंग होम में मरने वालों को संख्या में शामिल करता है, जबकि कैलिफोर्निया नहीं करता। अब तक अमेरिका में मरने वालों की संख्या 50 हजार को पार कर चुकी है।

जहां अस्पताल में मौतें हो रही हैं, वहां जरूरी नहीं कि हर मौत को सूची में जोड़ा ही जाए। बेल्जियम, ब्रिटेन, इटली, लक्जमबर्ग, दक्षिण कोरिया और स्पेन ने तय किया है कि यदि मरने वाले व्यक्ति का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव रहा हो, तो उसे सूची में जोड़ा ही जाएगा, फिर चाहे मौत पहले से चल रही किसी बीमारी के कारण ही क्यों ना हुई हो। इसके विपरीत ईरान ऐसा नहीं करता। यहां तक कि पॉजिटिव टेस्ट कर चुके व्यक्ति की मौत सांस की किसी और दिक्कत से हुई हो, तो भी उसे सूची में नहीं जोड़ा जाता है। अमेरिका में लोग शिकायत कर रहे हैं कि जब टेस्ट आसानी से उपलब्ध नहीं था, तब कई लोगों की मौत की वजह निमोनिया बताई गई और उन्हें सूची में शामिल नहीं किया जबकि निमोनिया कोरोना के कारण होता है। फ्रेंच इंस्टीट्यूट फॉर डेमोग्राफिक स्टडीज के गिलेस पाइसन और फ्रांस मेस्ले के अनुसार महामारी के दौरान जितनी भी तेजी से काम करने की कोशिश की जाए लेकिन सटीक जानकारी जमा करने में वक्त लगता है। उन्होंने कहा, "यह ठीक तरह से समझने में कई हफ्ते या कई महीने लग सकते हैं कि कितनी मौतें हुई होंगी।

अमेरिका में अगर मौत से पहले व्यक्ति का कोरोना टेस्ट नहीं हुआ था और डॉक्टर को कोरोना का शक है तो वह मृत्यु प्रमाणपत्र पर कोविड-19 को "संभावित कारण" बता सकता है। लेकिन इसे आधिकारिक रूप से कोरोना के कारण हुई मौतों की सूची में शामिल नहीं किया जा सकता। इसी तरह से स्पेन में भी मौत से पहले अगर टेस्ट नहीं हुआ था तो उसे सूची में दर्ज नहीं किया जा सकता। स्पेन का कहना है कि वह फिलहाल मौत के बाद टेस्ट करने की हालत में नहीं है। मार्च में न्यायिक अधिकारियों ने कॉस्टिला ला मांचा इलाके में जो आंकड़े पता लगाए, वे स्वास्थ्य अधिकारियों के आंकड़ों से तीन गुना ज्यादा थे। वहीं, जर्मनी में कुछ राज्यों ने मौत के बाद भी टेस्ट किए लेकिन हर राज्य के अलग नियमों के चलते ऐसे मामलों की कोई साझा सूची नहीं बन सकी।

कई देशों पर तो असली आंकड़े छिपाने और झूठ बोलने के आरोप भी लग रहे हैं। अमेरिका लगातार ईरान पर आंकड़े छिपाने के आरोप लगाता रहा है। चीन के आंकड़े तो दुनिया भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। कई हफ्तों तक संख्या कम दिखाने के बाद 17 अप्रैल को चीन के आंकड़े में अचानक ही 40 फीसदी का उछाल देखी गई। वुहान, जहां से इस वायरस की शुरुआत हुई, वहां के 1300 और मामले जोड़े गए। सरकार ने कहा कि घर में मौत होने के कारण इन लोगों को पहले सूची में जोड़ा नहीं जा सका था।ऐसे में आधिकारिक तौर पर भले ही दुनिया में अब तक दो लाख लोगों की जान गई हो लेकिन असली आंकड़ा कई गुना ज्यादा हो सकता है। इस संकट के खत्म हो जाने के बाद भी शायद वैज्ञानिक एक अनुमान मात्र ही बता सकेंगे। असली संख्या हमेशा एक पहेली बनी रहेगी। ●

कोरोना के आंकड़े कम आना और ज्यादा भयावह

सफदरजंग अस्पताल के सामुदायिक मेडिसिन विभागाध्यक्ष डॉ. जुगल किशोर का कहना है, लोग आंकड़ों से डर रहे हैं, लेकिन यह ऐसी प्रक्रिया है जिसे लोगों में पैनिक के चलते रोका नहीं जा सकता। जांच तेजी से हो रही है तो मरीज भी तेजी से सामने आ रहे हैं। अगर यह आंकड़े नहीं बढ़ेंगे तो महामारी को नहीं रोक पाएंगे।

एक वैज्ञानिक बताते हैं कि ऐसा नहीं कि कोरोना को समझने में हमसे भूल नहीं हुई। जनता कर्फ्यू के बाद लॉकडाउन हुआ तो 3-4 दिन बाद तब्लीगी जमात की खबर मिल गई। फिर प्रवासी मजदूरों का पलायन, जो अभी भी चुनौती बना हुआ है। कंटेनमेंट जोन पर गहन अध्ययन के साथ राज्यों को जानकारी दी गई, पर एक सच यह भी है कि उससे जुड़े दिशा निर्देशों पर सही अमल भी नहीं हुआ, जिससे सर्विलांस में रुकावट भी आई है।

आईसीएमआर के महामारी विशेषज्ञ बताते हैं कि विज्ञान में महामारी के विकास को अलग नजरिए से देखा जाता है। महामारी का घुमावदार ग्राफ यानी कर्व होता है, जो एक वक्त तक ऊपर बढ़ता है, फिर यह तेजी से नीचे जाने लगता है। यह प्रक्रिया कोरोना संक्रमण में भी चल रही है। ज्यादातर देशों में यह कर्व नीचे बढ़ने लगा है लेकिन भारत में अभी यह ऊपर की ओर ही बढ़ रहा है। इसे नीचे की ओर घूमने में कम से कम दो से चार सप्ताह लग सकते हैं। इसीलिए विशेषज्ञ जून से जुलाई के बीच देश में कोरोना का शीर्ष आने की उम्मीद जता रहे हैं।

256 जिलों में जल संकट ,मानसून को लेकर बनी रणनीति

मुरलीधर

नई दिल्ली:देश के 256 जिले जल संकट से जूझ रहे हैं। मानसून को लेकर यहां व्यापक रणनीति बनाई गई है। इस साल मानसून में सामान्य बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है।

'जल शक्ति अभियान' ने वर्तमान स्वास्थ्य संकट से उबरने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए पूरी तरह तैयारी की है। इस साल कोविड-19 संकट और ग्रामीण क्षेत्रों में भारी श्रम बल की उपलब्धता को देखते हुए आगामी मॉनसून के मद्देनजर अभियान के तहत तैयारियां शुरू कर दी गई है।

इस क्रम में ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन, नदी विकास, गंगा संरक्षण विभाग, भूमि संसाधन विभाग और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा इस साल आने वाले मानसून के मद्देनजर सभी राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को संयुक्त परामर्श जारी किया। साथ ही जल संरक्षण और पुनः संग्रहण के लिए की जाने वाली तैयारियों के बारे में अवगत कराया है।

बतातें चलें कि बीते साल जल शक्ति अभियान का शुभारंभ किया गया था। इसके दायरे में जल संकट से जूझ रहे देश भर के 256 जिले शामिल थे। यह अभियान सभी हितधारकों को जल संरक्षण अभियान के दायरे में लाने के लिए शुरू किया जनांदोलन है। बीते साल इसका देशव्यापी असर पड़ा था। राज्य सरकारों, केंद्र सरकार, सामाजिक संगठन, पंचायती राज संस्थान और समुदायों सहित साढ़े छह करोड़ लोग इस अभियान से जुड़ गए हैं। 75 लाख पारंपरिक और अन्य जल स्रोत तथा तालाबों का जीर्णोद्धार किया गया। लगभग एक करोड़ जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन ढांचे तैयार किए गए। प्रतिक्रियाओं के आधार पर इस साल के लिए ज्यादा व्यापक और ज्यादा मजबूत रणनीति बनाई गई थी। हालांकि मौजूदा स्वास्थ्य संकट को देखते हुए केंद्र सरकार के अधिकारियों को इन गर्मियों में इस अभियान में नहीं लगाया जाएगा। इस क्रम में सुनिश्चित किया जाएगा कि इस साल मानसून के दौरान वर्षा जल के संरक्षण के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया जा सके। इसके साथ ही तैयारियों से संबंधित गतिविधियों को भी पूरा कर लिया गया है।गृह मंत्रालय ने सिंचाई और जल संरक्षण कार्यों को देखते हुए लॉकडाउन के दौरान प्राथमिकता के आधार पर मनरेगा कार्यों/ पेयजल तथा स्वच्छता कार्यों को कराए जाने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। केंद्र और राज्य क्षेत्र की योजनाओं में मनरेगा कार्यों के साथ उपयुक्त सामंजस्य के साथ सिंचाई और जल संरक्षण क्षेत्रों को शामिल किए जाने के लिए स्वीकृति दे दी गई है। साथ ही, सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी कार्यों को सामाजिक दूरी के नियमों का पालन, फेस कवर/ मास्क के उपयोग और अन्य आवश्यक सावधानियों के साथ कराया जाए। पारंपरिक जल स्रोतों का जीर्णाद्धार, जल स्रोतों से अतिक्रमण हटाए जाने, झीलों और तालाबों से गाद निकालने, प्रवेश/ निर्गम मार्गों के निर्माण/ मजबूत बनाना, जल ग्रहण क्षेत्र की मरम्मत जैसे कार्य प्राथमिकता के आधार पर किए जा सकते हैं। इसी प्रकार छोटी नदियों के जीर्णोद्धार के लिए सामुदायिक नदी बेसिन प्रबंधन प्रक्रियाओं की भी शुरुआत की जा सकती है। ऐसी गतिविधियों से ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्रोतों का स्थायित्व सुनिश्चित होगा।

जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लागू किए जा रहे जल जीवन मिशन को मजबूती मिलेगी। जल जीवन मिशन के लिए स्थानीय समुदायों द्वारा तैयार ग्राम कार्य योजना (वीएपी) इसके अलावा ग्रामीण गतिविधियों के लिए ठोस तंत्र उपलब्ध कराया जाएगा। ●

अम्फान चक्रवात से निबटने को तैयार भारत

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, चक्रवात 20 मई की दोपहर या शाम को दीघा और हटिया के बीच सुंदरवन के करीब गिरेगा, जिसकी रफ्तार 165 से 185 किलोमीटर प्रतिघंटा हो सकती है। प्रधानमंत्री ने चक्रवात के मद्देनजर एक उच्चस्तरीय बैठक कर तैयारियों का जायज़ा लिया। बैठक में तैयारियों के संबंध में एनडीआरएफ ने बताया कि एनडीआरएफ की 25 टीमें ग्राउंड पर मुश्तैद हैं जबकि 24 टीमों को स्टैंड बाई पर रखा गया है। ओ-डिशा के तटवर्ती इलाकों मसलन जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा, जाजपुर, भद्रक, बालासोर और मयुरभंज में 18 मई को भारी बारिश की आशंका व्यक्त की है जबकि 19 और 20 मई को छिटपुट इलाकों में भारी बारिश हो सकती है, क्योंकि तब तक तूफान पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच पहुंच जाएगा।

इस तूफान के चलते 19 मई को पश्चिम बंगाल के गंगातटवर्ती जिलों पूर्व मिदनापुर और दक्षिण तथा उत्तर 24 परगना में मामूली से सामान्य बारिश होगी जबकि 20 मई को पूर्व व पश्चिम मिदनापुर, उत्तर व दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, हुगली, कोलकाता और समीपवर्ती इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। मछुआरों को आगाह किया गया है कि वे 18 से 20 मई के बीच मछलियां पकड़ने के लिए समुद्र में गहरे न जाएं।

झारखंड में कोई पैदल अपने घर न जाये: हेमंत सोरेन

रांची :मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि सभी जिला के अधिकारी एवं झारखण्ड पुलिस यह सुनिश्चित करे कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो झारखण्ड का हो या दूसरे राज्य का झारखण्ड में पैदल अपने गंतव्य को ना जाये। सभी अधिकारी पूरी संवेदनशीलता के साथ ऐसे सभी लोगों की पूरी देखभाल करते हुए समूह बना, उनकी स्वास्थ्य जाँच कर बसों व अन्य बड़े वाहनों द्वारा उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाएं। अन्य राज्य के प्र-वासियों का भी पूरा ख्याल रखते हुए उन्हें उनके गृह राज्य के नोडल पदाधिकारी से सम्पर्क कर सुरक्षित भेजने का प्रबंध करें। झारखण्ड की सीमा में किसी भी श्रमिक को कोई परेशानी ना हो इसका पूरा ध्यान रखना हमारा कर्त्तव्य है।

आदेश के अनुपालन को प्राथमिकता :मुख्यमंत्री के आदेश के बाद पुलिस महानिदेशक एमवी राव ने सभी पुलिस अधीक्षक/वरीय पुलिस अधीक्षक को अपने उपायुक्तों से समन्वय स्थापित कर निर्देशों का अनुपालन प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराने हेतु निदेश दिया है।

सभी पैसेंजर ट्रेन सेवाएं दिनांक 31 मई तक रद्द

रांची : कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के प्रयासों को जारी रखते हुए रेलवे मंत्रालय द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है की भारतीय रेलवे की सभी पैसेंजर ट्रेन सेवाएं दिनांक 31/05/2020 तक रद्द रहेगी। चूँकि संपूर्ण भारतवर्ष में दिनांक 31/05/2020 तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है। सभी लम्बी दूरी वाली मेल / एक्सप्रेस तथा इंटरसिटी ट्रेने (प्रीमियम ट्रेने भी) एवं सभी पैसेंजर ट्रेनें पहले दिनांक 17/05/2020 तक रद्द थीं अब यह सभी ट्रेनें 31/05/2020 तक रद्द रहेगी। इसी के अंतर्गत रांची रेल मंडल से चलने वाली सभी पैसेंजर ट्रेन सेवाएं अब 31/05/2020 तक रद्द रहेंगी।

रांची का देवड़ी बना एलोवेरा विलेज

संवाददाता

रांची के नगडी प्रखंड का देवडी गांव राज्य के एकमात्र एलोवेरा विलेज के रूप में विकसित हो चला है। दो वर्ष पहले वानिकी संकाय, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय तहत संचालित आईसीएआर- टीएसपी औषधीय पौध योजना के परियोजना अन्वेषक डॉ कौशल कुमार के तकनीकी मार्गदर्शन में गांव में एलोवेरा विलेज स्थापित करने का पहल किया गया। इसके संचालन में गांव की महिला मुखिया व कृषक श्रीमति मंजु कच्छप के प्रयासों का उल्लेखनीय योगदान है। विश्वविद्यालय की ओर से श्रीमति मंजु कच्छप के नेतृत्व में गांव के करीब 35 जनजातीय लोगों प्रशिक्षण देकर जागरूक किया गया। प्रशिक्षण उपरांत गाँव में एक ग्रीन हाउस सुविधा तथा लाभुकों को जैविक खाद एवं करीब 6 हजार पौध सामग्री वितरित किया गया। यूजीसी वीवोक इन हर्बल रिसोर्स टेकनोलोजी के छात्र - छात्राओं की सहभागिता से गाँव में पौध रोपण कार्यक्रम चलाया गया। गाँव में लोगों ने घर-आँगन, बेकार पड़ी भूमि और ग्रीन हाउस में पौधों को लगाया।

आज गाँव में मंजु कच्छप के साथ 18 जनजातीय किसान एलोवेरा सफल खेती से जुड़े है। एलोवेरा पौधा तैयार होने में करीब 18 माह का समय लगता है। आज इनके यहां लगा लगभग हर पौधा हरा - भरा, मोटी पत्तियों युक्त एवं गुद्दे से भरा है। एक - एक पत्तियों का वजन औसतन आधा किलो के करीब है।

बढ़िया गुणवत्ता युक्त पौध सामग्री होने से इनका उत्पाद स्थानीय स्तर पर ही बिक जाता है। ग्रामीणों के उत्पादों को विश्वविद्यालय ने भी क्रय कर दुमका जिले के विभिन्न गांवों में वितरित किया है। गत 4-5 महीनों में गांव वालों ने अबतक करीब दो हजार पौधों की बिक्री कर चुके है। ग्रामीणों द्वारा पोली बैग में प्रति पौधा 25-30 रू। तथा बिना पोली बैग का 15-20 रू। में बेचा जाता है। इसकी खेती से लोगों की आमदनी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आस - पास के ग्रामीण भी इसकी खेती में रुचि लेकर लाभ ले रहे है। देवड़ी गांव के ग्रामीण मंजु कच्छप के प्रयासों की सराहना करते है। अब झारखण्ड का देवड़ी गांव को एलोवेरा विलेज के रूप में जाना जाने लगा है। मंजु कच्छप बताती है कि आज गांव में बिक्री हेतु 100 किलो एलोवेरा का पत्ता और एक हजार पोली बैग बिक्री हेतु उपलब्ध है। एलोवेरा के पल्प से बने जुस का लीवर रोग, जोड़ो के दर्द एवं उदर विकार के उपचार में होता है। इस जुस की बाजार में अच्छी कीमत मिलती है। एलोवेरा पल्प के प्रसंस्करण हेतु सुविधा मिले तो यह ग्रामीणों के लिए बेहद लाभकारी व्यवसाय साबित हो सकता है। पौध की प्राप्ति के लिए महिला एलोवेरा कृषक समिति, देवडी ग्राम, नगडी, रांची से संपर्क किया जा सकता है।

मंजु कच्छप को उत्कृष्ट सामुहिक प्रयास कार्य के लिए विश्वविद्यालय ने सम्मानित भी किया है। परियोजना अन्वेंशक डॉ कौशल कुमार ने बताया कि एलोवेरा के पत्ती के जेल को सेनेटा-ईजर बनाने में भी उपयोग में लाया जा रहा है। मंजु कच्छप के मार्गदर्शन में ग्रामीणों ने एलोवेरा विलेज स्थापित कर एक मिशाल पेश किया है। एलोवेरा का पौधा कम पानी और कम उर्वर मिट्टी में भी आसानी से पनप सकता है। इसे बड़ी आसानी से घर के आंगन एवं छोटे-छोटे गमलों में भी उगाया जा सकता हैं।

एलोवेरा का सेनेटाईजर बनाने में उपयोग

कोरोना संकट की घडी में एलोवेरा (घृत कुमारी) की मांग दिन प्रतिदिन बढी है। एलोवेरा जेलमें रुब्बिंग आईसोप्रोपाइल अल्कोहल ,सुगंधित तेल को मिश्रित कर सेनेटाईजर बनाया जाता है।

एलोवेरा के गुण :एलोवेरा को एंटीऑक्सिडेंट में समृद्ध कहा जाता है। इसमें एंटीऑक्सिडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। इसके पौधे में मौजूद यौगिक पॉलीफेनोल्स की वजह से यह त्वचा और बालों के स्वास्थ्य सुधार में उपयोग होता है।

एलोवेरा के फायदे :एलोवेरा को घृत कुमारी या ग्वारपाठा के नाम से भी जाना जाता है। यह औषधीय पौधे के रूप में विश्व विख्यात है। इसका उल्लेख आयुर्वेद के ग्रंथों में भी मिलता है। इसके अर्क का प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन और त्वचा क्रीम, मधुमेह के इलाज, रक्त शुद्धि, मानव रक्त में लिपिड स्तर को घटाने में किया जाता है। एलोविरा और मशरूम से बना कैप्सूल एड्स रोगियों में लाभदायक पाया गया हैं।

राकेश रोशन ने बीएयू निदेशक प्रशासन का पुनः प्रभार लिया

संवाददाता

रांची :बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची के निदेशक प्रशासन का पुनः प्रभार शनिवार को झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी राकेश रोशन ने ग्रहण किया। राकेश रोशन को तत्कालीन कुलपति ने 7 अप्रैल, 2018 को निदेशक प्रशासन के प्रभार से विरमित कर दिया था। इस आशय का आदेश कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड की पूर्व अधिसूचना के आलोक में कृषि सचिव ने शुक्रवार को जारी किया है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा निदेशक प्रशासन का पद रिक्त होने और पदस्थापना के अनुरोध के बाद यह आदेश जारी किया गया।

राकेश कुमार कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड सरकार में संयुक्त सचिव है। उन्हें बीएयू निदेशक प्रशासन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। प्रभार लेने के बाद उन्होंने बताया कि यह विश्वविद्यालय राज्य की बड़ी धरोहर है, कई वजहों से विश्वविद्यालय अपने ट्रैक मै नहीं है। नियम सम्मत कार्यो से विश्वविद्यालय को सुदृढ़ करने का प्रयास होगा। राज्य सरकार के निर्देशों का अनुपालन होगा. उन्होंने पदाधिकारियों / कर्मियों को नियम सम्मत कार्य में सभी संभव सहयोग देने और मिल जुलकर विश्वविद्यालय हित में कार्य करने की बात कही. मौके पर डॉ आरएस कुरील, डॉ सोहन राम, डॉ पंकज सेठ, प्रो डीके रूसिया, जेपी तिवारी, लाल शाहदेव भी मौजूद थे। विश्वविद्यालय कर्मियों ने राकेश रोशन को प्रभार लेने पर बधाई दी है। उनके नेतृत्व एवं प्रशासनिक क्षमता से विश्वविद्यालय के लंबित समस्यायों के समाधान की आशा जताई है।

भारत निवेश के लिए बड़े सुधार कार्ड खेल रहा है: दीपक सूद

वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा अनावरण किए गए रक्षा उत्पादन, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, नागरिक उड्डयन और वाणिज्यिक कोयला खनन जैसे सबसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक क्षेत्रों में प्रमुख नीतिगत निर्णय आज निर्भीक आर्थिक सुधारों के दौरान नरेंद्र मोदी सरकार के दृढ़ संकल्प को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं। ये बातें कोविद - 19 वैश्विक स्वास्थ्य संकट पर एसोचैम के महासचिव दीपक सूद ने कही। रक्षा उत्पादन में एफडीआई सीमा को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने जैसे दूरगामी सुधारों की घोषणा की जाए, जिससे निजी क्षेत्र के लिए वाणिज्यिक कोयला खनन की अनुमति दी जा सके, केंद्रशासित प्रदेशों और उससे ऊपर के क्षेत्रों में निजीकरण को समाप्त किया जा सके।

एसोचैम के महासचिव ने कहा कि सभी देश की अंतरिक्ष क्षमताओं का व्यावसायिक रूप से उपयोग करने के लिए भारत के निजी क्षेत्र में आत्मविश्वास दोहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रमुख नीतिगत सुधारों पर आज की घोषणाएं, कोविद -19 की मानव और आर्थिक लागतों से निपटने के लिए प्रधान मंत्री के 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज के पिछले तीन चरणों के साथ मिलकर 130 करोड़ भारतीयों को एक विश्वास दिलाती हैं, केंद्र और राज्यों दोनों में एक मजबूत और एकजुट नेतृत्व के साथ, किसी भी संकट से साहस के साथ निपटा जा सकता है। यह जानकारी हम सब में है कि एक राष्ट्र के रूप में, हम एक संकट का सामना करते समय बहुत अच्छी तरह से प्रतिक्रिया करते हैं।कोरोना महामारी एक बार पूरे विश्व के लिए स्मृति संकट है। इसलिए, आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे की कमी के बावजूद विकासशील देश, भारत ने नेतृत्व का एक मजबूत उदाहरण पेश किया है। राजनीतिक स्पेक्ट्रम में कटौती, जिस तरह से राज्यों ने राष्ट्रीय आह्वान का जवाब दिया है उसे भी सराहा जाना चाहिए, दीपक सूद ने कहा कि संकट के समय सरकार के साथ खड़े होने के लिए इसका श्रेय आम पुरुषों और महिलाओं को भी दिया जाना चाहिए। ।

उन्होंने कहा, स्टॉक लिस्टिंग के विकल्प के साथ ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज के कॉरपोरेटाइजेशन और डिफेंस प्रोडक्शन के लिए घरेलू कंपनियों की सकारात्मक सूची जैसे फैसले भारत को हथियारों के आधुनिकीकरण और आधुनिक सहूलियत के लिए आत्मनिर्भर बनाने में बहुत मदद करेंगे।" सबसे सराहनीय बात यह है कि सबसे कठिन चुनौतियों में से एक से जूझते हुए, सरकार आगे की ओर सोच रही है और दृढ़ विश्वास के साथ साहसिक निर्णय ले रही है कि निवेश होगा। कोविड -19 संकट ने हमें, एक राष्ट्र के रूप में और मजबूत बनाया है और हम तेजी से सुधारो के पथ पर बढ रहे हैं।

यह स्थिति अमानवीय एवं संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है : हेमन्त सोरेन

संवाददाता

रांची :मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने उत्तर प्रदेश के औरैया में सड़क हादसे में मृत श्रमिकों के पार्थिव शरीर को एक ट्रक के जरिये झारखण्ड भेजने को अमानवीय एवं संवेदनहीनता की पराकाष्ठा कहा है। मुख्यमंत्री ने उपायुक्त बोकारो और झारखण्ड पुलिस को निदेश दिया है कि झारखण्ड की सीमा में प्रवेश करते ही ट्रक से आ रहे घायलों का उचित इलाज सुनिश्चित करें। साथ ही मृतकों के पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ उनके घर तक पहुँचाने का प्रबंध कर सूचित करें।

हम गरिमापूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे

मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि झारखण्ड के घायल एवं मृत प्रवासी श्रमिकों के लिए झारखण्ड की सीमा तक परिवहन की बेहतर व्यवस्था करें। झारखण्ड की सीमा पर राज्य सरकार उनके लिए गरिमापूर्ण व्यवस्था करेगी।

यह मिली थी जानकारी

मुख्यमंत्री को तस्वीरों और वीडियो साझा कर बताया गया कि औरैया हादसा में मरने वाले झारखंड के प्रवासियों के शवों को एक ट्रक पर बोकारो के चास स्थित घर भेजा जा रहा है। साथ में बचे लोगों का कहना है कि बर्फ की सिल्लियां पिघलने के बाद शव की स्थिति बिगड़ती जा रही है। ज्ञात हो कि यूपी के औरैया में झारखंड आ रहे मजदूरों से भरी ट्रक की दूसरे ट्रक से टक्कर हो गयी थी जिसमें 24 मजदूरों की दुखद मौत हो गयी थी। इस हृदयविदारक दुर्घटना में चूना लगे ट्रक से टक्कर के कारण मृत मजदूरों के शव चूने के बोरियों में दब गये थे जिन्हें बहुत ही मुश्किल से निकाला गया था। उसके बाद उत्तर प्रदेश प्रशासन ने मजदूरों के शवों को सम्मान से एंबुलेंस में भेजने के बजाय ट्रक में लाद कर झारखंड भेज दिया।

रांची रेल मंडल ने 800 लोगों को भोजन कराया

संवाददाता रांची :17 मई को रांची रेल मंडल ने विभिन्न स्थानों पर 800 गरीब तथा जरूरतमंद व्यक्तियों में भोजन का वितरण किया और कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए संपूर्ण देश को लॉक डाउन किया गया है ,कारणवश गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है । इन कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए रांची रेल मंडल प्रतिदिन विभिन्न स्थानों पर गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन उपलब्ध करा रहा है।

रेल सुरक्षा बल रांची पोस्ट तथा आईआरसीटीसी द्वारा सिमर टोली अरगोड़ा में गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन का वितरण किया गया तथा कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। रेल सुरक्षा बल, हटिया पोस्ट, तथा आईआ-रसीटीसी द्वारा हटिया स्टेशन रोड, तीतर टोली, गिरजा टोली और हवाई नगर एरिया में गरीब तथा जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन का वितरण किया गया तथा कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया।

गर्मी और बरसात में मवेशियों का परजीवी रोगों से बचाव जरूरी

संवाददाता

गर्मी और बरसात के महीनों में रक्त परजीवी रोगों से मवेशियों का बचाव किया जाना जरूरी है। इस मौसम में मख्खियों और बाह्य परजीवियों की तादाद बढ़ने से रक्त परजीवी रोग जैसे थैलेरिया, बैबेसिया, सर्रा एवं रक्त जीवाणु रोग जैसे एनाप्लाज्मा का अधिक प्रकोप होता है। समय से उपचार नहीं होने पर यह रोग मवेशियों के मृत्यु का कारण बन जाता है। इन रोगों का संक्रमण देशी नस्लों की तुलना में संकर तथा विदेशी नस्लों के मवेशियों में अधिक होता है।

रोग के लक्षण

तेज बुखार और शरीर का तापमान 105 - 108 डिग्री एफ। तक होना इनके सामान्य लक्षण है। थैलेरिया रोग में मवेशियों के अगले और पिछले पैर के पास बड़ा लिम्फ ग्रंथि (गांठ), शरीर में खून की कमी और बीमारी बढ़ने पर काला खुन युक्त गोबर का होना।

बैबेसिया रोग से ग्रस्त मवेशियों द्वारा खुन पेशाब करना, पेशाब का रंग बिना दुध वाले कॉफ़ी जैसा होना, पेशाब और गोबर के रंग में पीलापन और अचानक 105 - 108 डिग्री एफ। तक बुखार का होना। सर्रा एक जटिल रोग है। इसमें बुखार के अलावा स्नायुतंत्र से सबंधित

लक्षण जैसे दीवार या नाद को सिर से ठकेलना, पगहा खींच खड़ा होना, गिर जाना, गोल-गोल घुमना व थरथराना दिखता है। भैंस में सर्रा रोग का खतरा अधिक होता है। एनाप्लाज्मा रोग में तेज बुखार, पेशाब और गोबर के रंग में पीलापन और शरीर में खून की कमी व 2-3 ग्राम प्रतिशत तक होमोग्लोबिन का घट जाता है।

बचाव के उपाय

गोहाल की प्रभावकारी दिन में 3 बार सफाई, मवेशी में मक्खियों और बाह्य परजीवियों का नियंत्रण, बीमारी को अधिक बढ़ने देना नहीं तथा पशु चिकित्सक से संपर्क कर मवेशियों की अविलंब चिकित्सा जरूरी होता है।

सावधानी

इन रोगों की मारक क्षमता अधिक होती है। उपचार में देरी से मवेशी की जान को खतरा बना रहता है। मवेशी के शरीर खासकर कान, पैर के अंदर का हिस्सा, गर्दन, पेट आदि में अठैल आदि के संक्रमण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है।

बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा संकाय के पशु रोग विभाग के अध्यक्ष डॉ एमके गुप्ता का कहना है कि बुखार का पता चलने पर मवेशियों के रक्त जाँच से सही रक्त परजीवी रोग का पता चलता है। परजीवी की पहचान से ही उचित दवा से बीमारी का नियंत्रण किया जा सकता है। रक्त का नमुना मवेशियों के दवा लेने से पहले का होना जरूरी है। रक्त जाँच का परिणाम धनात्मक होने पर पुनः 1-2 दिनों के बाद रक्त की जाँच करानी चाहिये। बुखार दीखने पर तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। संकाय स्थित विभाग में पशुओं के खुन और पेशाब की निः शुल्क जाँच सुविधा उपलब्ध है।

फसल पर कीड़ो का प्रकोप ,वैज्ञानिकों ने दी सलाह

संवाददाता

रांची : प्रदेश में हो रही बारिश से गरमा फसलों एवं लत्तीदार सब्जियों में हानिकारक कीटों का प्रकोप बढ़ गया है। अभी खेतों में गरमा फसलों में मुंग व मकई,सब्जियों में नेनुआ, खीरा, लौकी, करैला,भिन्डी,टमाटर,शिमला मिर्च आदि लगे हुए है। किसान कीटों के आक्रमण से बचाव के लिए कीट वैज्ञानिकों से जानकारी ले रहे। इसे देख बीएयू के कीट विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉ पीके सिंह ने किसानों के लिए परामर्श जारी किया हैं।

मौसम में बदलाव के कारण मूंग की फसल में थ्रिप्स कीडा का प्रकोप देखा जा रहा है। जो मूंग के फुल का रस चुसकर नुकसान पहुँचाता है। इससे फुल पौधे से गिर जाते है। दुसरी कीट सफ़ेद मख्खी का प्रकोप भी खेतों में देखा जा रहा है, जो आकार में काफी छोटी होती है और इसे सुबह के समय पत्तियों के नीचे देखा जा सकता है। यह कीट पत्तियों का रस चुसकर नुकसान पहुँचाता है तथा पौधे पर पीला मौज़ेक बीमारी फैलाता है। जब यह बीमार पौधे को खाकर स्वस्थ्य पौधे को खाती है, तब पीला मौज़ेक बीमारी का फैलाव होता है। इन दोनों कीटों के बचाव में विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। सबसे पहले खेतों में पीला मौज़ेक रोग से ग्रषित पौधे को उखाड़कर दुसरे जमीन में गाडकर नष्ट कर देते है। फसल पर एक ग्राम थाईमेथाकसम को तीन लीटर पानी में घोल कर या एक मि। ली। इमिडाक्लोराइड को दो लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें।

खेत में लगे मूंग में यदि फली आ गई हों तथा कीट फली में छेदकर खाकर नुकसान कर रहा हो तो, इंडोएस्कार्ब 14।5 एससी या स्पाईनोसाइड 45 एससी नामक दवा का एक मि। ली। को 2 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना लाभप्रद होगा। खेत में तीन सप्ताह का खड़ी गरमा मकई फसल में तना छेदक कीट का आक्रमण देखा जा रहा है । इस कीट का पिल्लु मकई पौधे के तना में छेदकर आतंरिक भागों को खा जाते है। इससे बचाव के लिए दानेदार कीटनाशी दवा फिप्रानिल 0।3 जी या कारबोफ्युरान 3 जी का 8 -10 दाना का व्यवहार पत्तियों के उपरी चक्र में करना लाभप्रद होगा। पत्तियों पर भूरे रंग के छोटे गोल व अंडाकार धब्बे व अनियमित आकार सबंधी पत्र लांक्षण रोग प्रकट होते ही मैनकोजैब 2।5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छि-ड़काव करें। पत्तियों एवं तनों पर भूरे व काले रंग के धब्बे वाली हरदा रोग का मैनकोजैब से ही उपचार किया जा सकता है।

खेत में खडी फसल में बाली निकलने की अवस्था में गंधी बग कीट के प्रकोप से बचाव के लिए कीटनाशी दवा क्लोरपाइरीफोस धुल या क्वीनॉल्फोस धुल या मिथाइल पराथियोन धुल का भुरकाव 10 किलो प्रति एकड़ की दर से शाम के समय मौसम साफ रहने पर करें। भुरकाव के बाद कीड़े बगल के खेतों में चले जाते है। इसलिए अलग - अलग खेतों में भुरकाव करना उत्तम होगा। कीटनाशी दवा नहीं रहने पर राख में मिट्टी या किरासन तेल मिलाकर खडी फसल पर भुरकाव किया जा सकता है।

समय पर बोया गया फसल यदि पुष्पावस्था में हो और फुल मुरझा कर गिर रहा हो तो, संभावित थ्रिप्स (चुरदे) कीट से बचाव के लिए कीटनाशी दवा ट्राइजोफोस या प्रोफेन्फोस का छिड़काव एक मि। ली। को प्रति लीटर पानी की दर से मिलाकर शाम के समय मौसम साफ रहने पर छिड़काव करें।

लत्तरदार सब्जियों जैसे नेनुआ, खीरा, लौकी, करैला तथा अन्य सब्जियों में भिन्डी, टमाटर, शिमला मिर्च आदि में लाल भृंग, फल मख्खी या लाल मकडी का प्रकोप देखनो को मिल रहा है। यदि पौधों में फल लगना शुरू हो गया हो तो, नीम से बना कीटनाशी जैसे अचुक/ नीमेरीन/ नीमेसिडीन में से किसी एक दवा का 5 मि. ली. को प्रति लीटर पानी में मिलाकर मौसम साफ रहने पर छिड़काव करना चाहिए।

फोटो न्यूज

मैदान में खेलते बच्चे : अब शाम में मैदान में युवाओं और किशोरों के खेलने का दृश्य कम ही देखने को मिलता है। स्मार्टफोन और कंप्यूटरों ने खेल को लील लिया है। मानसिक शारीरिक स्वास्थ के लिये जरूरी खेल मैदान भी अब धीरे धीरे शहरों में सिकुड़ते जा रहे हैं।

मजेदार गतिविधियों के साथ करें कैलोरी बर्न

ऋतु सिंह, योग प्रशिक्षक

वज़न को कम करने या नियंत्रित रखने के लिए रोज़ हमें कैलोरी बर्न करना जरूरी है। रोज के वर्क- आउट से हम कभी-कभी बोर हो जाते हैं और वर्क आउट बेक्र ले लेते हैं , तो आइए देखते हैं कि वर्क आउट बेक्र लेने से अच्छा कुछ मज़ेदार तरीकों से कैलोरी बर्न करें।

✓खरीदारी- खरीदारी चाहे शॉपिंग मॉल में हो या रोड साइड के दूकान में हो ये कैलोरी बर्न करने में बहुत ही सहायक है।अगर हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो कम से कम दो-तीन घंटे सक्रिय रहते हैं जिससे काफी कैलोरी बर्न हो जाती है।

✓रस्सी कूदना- रस्सी कूदना काफी मज़ेदार तरीका है कैलोरी बर्न करने के लिए, बच्चे रस्सी कूद को एक खेल की तरह खेलते हैं , तो खेल खेल में भी काफी कैलोरी बर्न हो जाती है और रेगुलर वर्क आउट भी हो जाता है।

✓साइकलिंग - साइकलिंग से भी काफी कैलोरी बर्न होती है। साइकलिंग करते समय आप अपने काफी निजी काम भी कर सकते हैं जैसे घर के आसपास के छोटे बड़े काम।

✓डांस करना- डांस एक बहुत ही मनोरंजक गतिविधी है और लगभग सभी लोग पसंद भी करते हैं। इसमें अलग-अलग प्रकार होते हैं जैसे कि क्लासि-ाकल डांस,फ्री स्टाइल आदि। डांस से काफी कैलोरी तो बर्न होती ही है , साथ-साथ टोनिंग और शरीर का लचीलापन भी बढ़ता है।

✓तैराकी- गर्मियों के दिनों में सबसे बेहतरीन व्यायाम तैराकी है । ये एक ऐसा व्यायाम है जो हर उम्र के लोग कर सकते हैं तो अगर आप रोज के वर्क- आउट से बोर हो गए हैं तो तैराकी कर के कैलोरी बर्न करें।

✓डॉग वॉक- अगर आपके पास कुत्ता है तो आप उसको वॉक पे ले जा सकते हैं इससे दो काम एक साथ हो जायेंगे मतलब आम के आम और गुठलियों के भी दाम। आपका डॉग खेलने और दौड़ने में व्यस्त रखेगा। इस तरह वॉक करके भी काफी कैलोरी बर्न होती है।

✓घर की साफ-सफाई- लॉकडाउन के समय घर की सफाई सबसे बड़ा वर्क आउट बन गया है,जब घरेलू सहायक उपलब्ध नहीं है। काफी कैलोरी घर के साफ़ सफाई में भी बर्न होती है ,और सबसे अच्छी बात ये है कि हमारा काम भी हो जाता है।

✓बच्चो के साथ खेलना-कूदना- ये सबसे अच्छा वर्क आउट है जो शरीर और मन दोनों को हल्का करता है।बच्चों को साथ खेलना भी बच्चों का खेल नहीं है मतलब काफी फुर्तीला रहना पड़ता है जब बच्चे साथ में हो।

जर्मनी में बूचड़खाने बने कोरोना के गढ़

एजेंसियां

जर्मनी में बूचड़खाने कोरोना वायरस के फैलाव के नए केंद्र बनकर सामने आ रहे हैं। दो हफ्तों के भीतर चौथे बूचड़खाने में दर्जनों लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं।

जर्मनी के एक और बूचड़खाने में सोमवार को कोरोना वायरस के बड़े फैलाव का पता चला। हाल के हफ्तों में देश के कई मीट प्रोसेसिंग प्लांट कोरोना वायरस की चपेट में आए हैं और सैकड़ों लोग संक्रमण का शिकार बने हैं। ताजा मामला लोवर सेक्सनी राज्य का है जहां एक बूचड़खाने के 92 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद संक्रमित लोगों को उनके घरों पर क्वारंटीन कर दिया गया है और मीट प्लांट में काम रोक दिया गया है।

सोमवार को जर्मन सरकार की "कोरोना कैबिनेट" की कार्यस्थल पर सुरक्षा नियमों पर बैठक होनी थी। लेकिन अब इसे बुधवार तक टाल दिया गया है। उम्मीद है कि इस

बैठक में मीट प्रोसेसिंग प्लांटों का मुद्दा खास तौर से उठेगा, जहां काम की परिस्थितियों को लेकर अकसर सवाल उठते रहे हैं। इन प्लांटों में ज्यादातर पूर्वी यूरोपीय देशों से आए अस्थायी कामगार काम करते हैं।

बेहाल बूचड़खाने :ऐसे ज्यादातर कामगार पोलैंड, रोमानिया और बुल्गारिया से आते हैं। उनके काम की खराब परिस्थितियों और रहन सहन के बारे में बरसों से बात होती रही है, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण से पहले कभी इस मुद्दे को इतनी गंभीरता से नहीं लिया गया। बीते दो हफ्तों में श्लेसविग होलस्टाइन और नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया जैसे जर्मन राज्यों में मीट प्रोसेसिंग प्लांटों को बंद कर दिया गया क्योंकि वहां 350 से ज्यादा कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके अलावा बवेरिया के एक बूचड़खाने में भी 60 लोग संक्रमित मिले।

बूचड़खाने में कोरोना वायरस

जो कर्मचारी स्वस्थ हैं, उनकी शिकायत है कि उन्हें अपने रहने की सीमित सी जगहों पर क्वारंटीन किया गया है और यह भी नहीं बताया जा रहा है कि उन्हें कब बाहर निकलने दिया जाएगा या फिर इस दौरान घर पर रहने के उन्हें पैसे दिए जाएंगे या नहीं। इस बीच, खाद्य और पेय पदार्थ यूनियन ने सरकार से कहा है कि इस मौके का इस्तेमाल करते हुए वह मीट उद्योग में "बुनियादी बदलाव" करे और बूचड़खानों को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जाएं। जर्मनी में बूचड़खानों में ऐसे समय में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, जब हफ्तों से जारी पाबंदियों में ढील दी जा रही है और धीरे धीरे आम जनजीवन और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिशें हो रही हैं।

अब स्वदेशी आधुनिक मिट्टी के बर्तन

राजन कुमार

अब स्वदेशी का जोर चल पड़ा है। ऐसे में रांची के लालपुर में मिट्टीकूल नामक एक शॉप में मिट्टी के हर प्रकार के बर्तन मिल रहे हैं। इन बर्तनों की खासियत है कि ये मिट्टी के तो हैं, पर मेटल के आधुनिक डिजाइन वाले बर्तनों को मात देते हैं। मिट्टी के केसरॉल, प्रेशर कुकर, फ्राइंग पैन, डिनर सेट सब कुछ उपलब्ध हैं।

पहले मिट्टी के बर्तनों मे ही भोजन पकाया जाता था जो स्वास्थ्य के लिये बहुत ही उतम होते थे। हम आज भी टीवी चैनलों में अच्छे शेफ को जब कोई डिश बनाते देखते हैं तो अक्सर उन्हें किसी मिट्टी के बर्तन का उपयोग करते देखते हैं। मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाने और खाने से जुड़ी इन बातों को जानना है बेहद जरूरी है।कई हजार साल से भारत में मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता रहा है क्योंकि मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाने से ऐसे पोषक तत्व मिलते हैं, जो हर बीमारी को शरीर से दूर रखते थे। इस बात को अब आधुनिक विज्ञान भी साबित कर चुका है कि मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाने से शरीर के कई तरह के रोग ठीक होते हैं। भोजन धीरे-धीरे ही पकना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार, अगर भोजन को पौष्टिक और स्वादिष्ट बनाना है तो उसे धीरे-धीरे ही पकना चाहिए। साथ ही भोजन में मौजूद सभी प्रोटीन शरीर को खतरनाक बीमारियों से सुरक्षित रखते हैं। भले ही मिट्टी के बर्तनों में खाना बनने में वक़्त थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन इससे सेहत को पूरा लाभ मिलता है। इसके अलावा आयुर्वेद में इस बात को भी बताया गया है कि जो भोजन धीरे-धीरे पकता है वह सबसे ज्यादा पौष्टिक होता है। जबकि जो खाना जल्दी पकता है वो खतरनाक भी होता है।

बेतला नेशनल पार्क में तीन जंगली भैसों की मौत

देवाशीष

रांची : राज्य के प्रसिद्ध बेतला नेशनल पार्क में तीन जंगली भैसों की मौत हो गयी है। कुछ दिनों पहले दो जंगली भैसो की मौत संक्रमण से हुई थी। बेतला नेशनल पार्क में तकरीबन छह दर्जन जंगली भैसे (बायसन) हैं। और संक्रमण से तीन भैसों की मौत से वन विभाग के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आयी हैं। क्योंकि अगर इस संक्रमण ने किसी महामारी का रूप लिया तो बेतला नेशनल पार्क की रौनक रहे इन जंगली भैसों पर खतरा मंडराने लगेगा। कुछ महिनों पहले इन्हीं जंगली भैसों के साथ मुठभेड़ में एक बाघिन की मौत हो गयी थी।

जंगली भैसों में घरेलु मवेशियों से भी संक्रमण फैलता है। किसी भी नेशनल पार्क के इर्द गिर्द के गावों से अक्सर पालतु पशुओं को चराने के लिये अवैध रूप से पार्क के इलाके में ले जाया जाता है। और इन्हीं पालतु पशुओं के संपर्क में आने के कारण ही पार्क के जंगली पशुओं में रोगों का संक्रमण होता है। किसी भी वन अभ्यारण्य में पालतु पशुओं और मवेशियों को चराने पर रोक है। मवेशियों के अभ्यारण्यों में घुस कर चरने से जंगली जानवरों में संक्रमण का खतरा होता है। पालतु जानवरों में किसी रोग के फैलने पर किसान या पशुपालक उसका इलाज करवा लेते हैं पर जंगली जानवरों में किसी रोग के होने पर उनका ईलाज बहुत मुश्किल होता है। और अगर ये बीमारी किसी भी कारण से महामारी का रूप ले लेता है तो वन्य प्राणियों की बड़ी आबादी का सफाया हो जाता है। अक्सर घरेलु गाय भैसों में होने वाला खुरहा रोग सबसे घातक होता है।

हालांकि बेतला नेशनल पार्क में यह तय नहीं है कि जंगली भैसों में रोग का संक्रमण किसी पालतु मवेशी से ही हुआ है, पर तीन जंगली भैसो की मौत से सभी चिंतित अवश्य हैं।

किसानों की मदद को आया वेजक्योर

मैं अमित जैन वेजक्योर का को फाउंडर हूं। लोकडॉन के दौरान जब मुझे यह मालूम पड़ा कि किसानों को उनके उत्पाद बेचने में बहुत परेशानी हो रही है तथा उनको उनके फल सब्जियों के उचित दाम नहीं मिल रहे हैं तो हमने सोचा कि क्यों नहीं जो किसान जैविक खेती करते हैं उनके उत्पादों को हम स्वयं खरीद कर लोगों को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराएं।

हमें सिद्धार्थ जयसवाल सर जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय मैं बिजनेस प्लानिंग और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सीईओ है का उचित मार्गदर्शन व निर्देशन प्राप्त हुआ। उन्होंने जैविक खेती में पिछले 15 सालों से काफी अनुसंधान किया है साथ ही हमें संपूर्ण कृषि उत्थान संस्थान के रवि सिंह चौधरी का भी बहुत सहयोग मिला। सिद्धार्थ जयसवाल जी ने हमें बताया की ओरमांझी के आरा कैरम गांव में पिछले 3 वर्षों से जैविक खेती उनके निर्देशन में कराई जा रही है और वहां के 50 किसानों को जैविक खेती का सर्टिफिकेट भी मिल चुका है तथा यह गांव पूर्ण रूप से नशा मुक्त, प्लास्टिक मुक्त व खुले में शौच मुक्त हैं। हम वहाँ के किसानों से मिले और उन्होंने हमें अपने जैविक उत्पाद उपलब्ध करवाये। हमने अक्षय तृतीया के दिन दिनांक 26 अप्रैल को जैन भवन हरमू रोड गौशाला के सामने अपना जैविक फल व सब्जियों का स्टॉल लगाया था हमें लोगों का बहुत साथ मिला, लोगों ने हमारे प्रयास को बहुत सराहा। फिर हमने बड़े-बड़े अपार्टमेंट्स जैसे मोदी कंपाउंड लालपुर ,रश्मिरथी अपार्टमेंट कांके रोड आदि जगह पर अपने जैविक फल और सब्जियों को उपलब्ध कराया। आगे हम लोगों को होम डिलीवरी की सुविधा भी देने का प्रयास करेंगे। जैविक फल व सब्जियों में केमिकल और कीटनाशकों द्वारा उगाई गए फल व सब्जियों से कई गुणा अधिक विटामिन्स व मिनेरल्स पाए जाते हैं और हमारी इम्युनिटी को बढ़ाने में सहयोग करते हैं।

गिलोय : रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी

अजय कुमार

रांची : देश के करीब प्रदेशों में गिलोय का पौधा पाया जाता है। बाबा रामदेव द्वारा गिलोय को डेंगू बीमारी में उपयोगी बताये जाने के बाद जन साधारण को इसके महत्त्व का पता चला। आज वैश्विक कोरोनो वायरस संक्रमण से बचाव के लिए कोई भी वैक्सीन पूरी दुनिया में उपलब्ध नहीं है। पूरी दुनिया इस वायरस के चिकित्सीय समाधान पर शोधरत है। कोरोनो संकट का आयुर्वेदिक औषधीय चिकित्सा के माध्यमों से भी समाधान ढुँढने का प्रयास हो रहा है। देश में लागु लॉक डाउन के बीच 27 अप्रैल से 2 मई तक चिकित्सा विज्ञान संस्था, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी ने 'कोरोना विषाणु संक्रमण में आयुष की वैश्विक भुमिका' विषय पर इंटरनेशनल वर्चुअल बेविनार का आयोजन किया। इस बेविनार में विभिन्न देशों के करीब 100 हर्बल मेडिसिन के विशेषज्ञ एवं दवा निर्माता कंपनी के प्रमुखों ने विडियो एप के माध्यम से भाग लिया। बेविनार में 9 बिन्दुओं के महामना डिकलेरेशन में गिलोय स्क्वाथ (काढा) को शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी बताया गया। गिलोय जुस के नियमित सेवन को शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता में बढ़ोत्तरी की बातें उभर कर आई। इस बेविनार में बिरसा कृषि वि-श्वविद्यालय के औषधीय पौध विशेषज्ञ डॉ कौशल कुमार ने भी विडियो एप के माध्यम से भाग लिया। उन्होंने विश्वविद्यालय के वानिकी संकाय के वनोत्पाद एवं वन उपयोगिता विभाग में संचालित आईसीएआर - एआईसीआरपी 'औषधीय एवं सुगंधित पौध' परियोजना के तहत गिलोय पौध शोध

पर चर्चा की। इस शोध में पूरे देश से एकत्रित किये गये गिलोय के 28 जर्मप्लाज्म की पौध विकास का आकलन, तना की गुणवत्ता की जाँच, मौसमी प्रभावों एवं अन्य प्रायोगिक विषयों पर शोध उपलब्धियों से अवगत कराया।

डॉ कौशल कुमार बताते है कि गिलोय एक बेजोड़ किस्म का अमृत तुल्य औषधीय पौधा है। इसके तना, पत्ते और जड़ का औषधि बनाने में उपयोग होता हैं। इसे आयुर्वेदिक द्रष्टिकोण से सबसे उत्तम औषधि के रूप में जाना जाता है। इसमें एंटीऑक्सिडेंट गुण मौजूद होने से इसे खतरनाक रोगों से लड़कर शरीर को सेहतमंद रखने में सहायक एवं किडनी और लीवर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालकर खुन को साफ करने में मददगार माना जाता है। लॉक डाउन के बाद परियोजना के अधीन आँगन - बूटी कार्यक्रम के आयोजन से गिलोय उगाने के लिए लोगों को जागरूक किया जायेगा और पौधा वितरण कार्यक्रम भी चलाया जायेगा।

गिलोय पौध उगाने के तरीके

गिलोय का पौधा जिस भी पेड़ पर चढ़ जाती है, उसके गुण को अपने भीतर चढ़ा लेती है। नीम पर चढ़ी हुई गिलोय सबसे उत्तम मानी जाती है। गिलोय के व्यावसायिक खेती ग्रीन हाउस में की जाती है। इसे घर-आँगन, गमले एवं बेकार पड़ी भूमि में भी उगाया जा सकता है।

गिलोय पौधे से उपचार

गिलोय के पत्तों को पानी में उबालकर उबले पानी का सेवन करना चाहिए। इसके डंठल के रस का प्रयोग उत्तम होता है। सीधे या अधिक मात्रा में सेवन से मुंह में छाले होने का डर बना रहता है। नीम और आंवला के साथ इसके इस्तेमाल से त्वचा संबंधी रोग जैसे एग्जिमा और सोराइसिस दूर किये जा सकते हैं। इसके रस को आंवले के रस के साथ देने से आंखों की रोशनी भी बढ़ती है एवं आंख से संबंधित रोग भी दूर होते हैं। यह वात, पित्त और कफ से होने वाली बीमारियों से छुटकारा दिला सकता है। आधा ग्राम गिलोय पाउडर को आंवले के चूर्ण के साथ नियमित सेवन से शरीर का पाचन तंत्र ठीक रहता है एवं शरीर में खून के प्लेटलेट्स की गिनती को बढ़ाने में सहायक होता है। गिलोय डायबिटीज के मरीजों के लिए वरदान है। हाथ की छोटी उंगली के बराबर गिलोय के तने का रस और बेल के एक पत्ते के साथ थोड़ी सी हल्दी मिलाकर एक चम्मच रस का रोजाना सेवन करने से डायबिटीज की समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके एक चम्मच रस में एक चम्मच शहद मिलाकर सुबह-शाम लेने से मोटापा दूर हो जाता है। इसके नियमित सेवन से पेट के कीड़े और कीड़े के कारण शरीर में खून की कमी को दूर किया जा सकता है। दो चम्मच गिलोय का रस हर रोज सुबह लेने से सर्दी - खांसी - जुकाम से राहत मिलती है।

E ZONE CARE

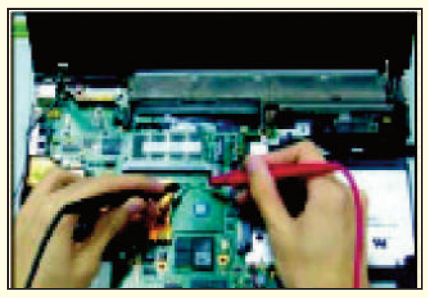

Software Problem, Motherboard Chip-Level Repair, Laptop AC Adapter Repair and Replacement, Laptop LCD Screens Repair and Replacement, Dead Laptop Problems, No Display Problem, LCD Dim Display Problem, LCD White Display Problem, BIOS Password Problem, all type of Laptop repair and service

• **Repair your laptop with 3-month warranty.**

info@ezonecare.in, ezonecare.in
Rospa Tower 3RD Floor, Main Road, Ranchi 93108 96575, 70047 69511
Mon - Fri 10:30 am - 7:00 pm
SUNDAY CLOSED

अखबार के स्वामी सन कम्युनिकेशन के लिये प्रकाशक मनोरंजन सिंह द्वारा प्रकाशित तथा मेसर्स डी. बी. कॉर्प लिमिटेड,प्लॉट नं535 एवं 1272 ललगुटवा पुलिस स्टेशन, रातू, रांची (झारखंड) से मुद्रित और सन कम्युनिकेशन,अपोजिट कब्रिस्तान गेट नं.-2, टीवीएस गली, रातू रोड, रांची-834001 (झारखंड) से प्रकाशित। संपादकः एम.के.शर्मा * (पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिये उत्तरदायी)आर.एन.आइ. पंजीयन क्रमांक : **JHAHIN/2019/78094**, email:greenrevolt2019@gmail.com. ☎ 0651-2283018, 8539978825, 8825374626. समस्त विवाद रांची न्यायालय के अधीन होंगे।